

दिल्ली
अधिकतम तापमान 26 डिग्री
न्यूनतम तापमान 13 डिग्री

एनसीआर
अधिकतम तापमान 26 डिग्री
न्यूनतम तापमान 12 डिग्री

रविवार 09 नवंबर 2025
सूर्योदय प्रातः 06:34 बजे
सूर्यास्त सांय 17:31 बजे

www.khabariya.com

एनसीआर टुडे

करंट न्यूज करंट व्यूज



पृष्ठ 4 अमीरी में अभिवृद्धि विद्रोह एवं संकट का बड़ा कारण

उत्तर प्रदेश और दिल्ली से एक साथ प्रकाशित वर्ष : 17 अंक : 023 गाजियाबाद, रविवार 09 नवंबर 2025 मूल्य : ₹ 2 पेज : 06 विक्रमी संवत् 2081 युगाब्द 5126 शाक 1946

केनडा बैंक Canada Bank

SCAN & PAY

UPI ID: 300012627000246@cnrb

BHIM UPI

Digitally signed by CNRB

NCR MASALA

India's Premium Masala

9410855900 ncrmasala@gmail.com

get online www.ncrmasala.com

गर्म मसाला, हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा व अन्य रसोई मसाले

प्रधानमंत्री ने 4 वंदे भारत ट्रेनों को दिखायी हरी झंडी

*** एनसीआर टुडे, वाराणसी ***

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चार नयी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मोदी ने यहां बनारस रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम में बनारस-खजुराहो ट्रेन को हरी झंडी दिखायी।

इसके अलावा उन्होंने वचुंअल माध्यम से लखनऊ-सहारनपुर, बंगलूरु-एनकुलम और फिरोजपुर कैंट - दिल्ली वंदे भारत प्रीमियम ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मोदी के साथ केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यादव भी थे।

विशेष पास पर ट्रेन में यात्रा कर रहे लोगों में काफी उत्साह दिखा। बड़ी संख्या में स्कूलों के बच्चे भी ट्रेन में थे। प्रधानमंत्री ने ट्रेन में बच्चों और ड्राइवर से भी बात की इसके साथ ही अब देश में वंदे भारत



ट्रेनों की संख्या 78 से बढ़कर 82 हो गयी है। उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया था जो नयी दिल्ली से वाराणसी के लिए चली थी। अब तक देश भर में विभिन्न मार्गों पर वंदे भारत ट्रेनों में सवा सात करोड़ से अधिक यात्री सफर कर चुके हैं। इसका विस्तार 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो चुका है।

श्री मोदी ने दुल्हन की तरह सजे बनारस रेलवे स्टेशन से खजुराहो जाने वाली उद्घाटन ट्रेन को हरी झंडी दिखायी। खास बात यह है कि यह प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से खजुराहो के लिए पहली नियमित ट्रेन है।

आम दिनों में वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत (26422) सुबह 5:25 बजे वाराणसी से रवाना होगी और दोपहर बाद 1:10 बजे खजुराहो पहुंचेगी। वापसी की

ठहराव सीतापुर, सीतापुर सिटी, 2:35 बजे दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद, रुड़की और सहारनपुर में होगा। यह सोमवार को छोड़कर सभी छह दिन चलेगी। केएसआर बंगलूरु-एनकुलम वंदे भारत (26651) सुबह 5:10 बजे बंगलूरु से चलकर दोपहर बाद 1:50 बजे एनकुलम पहुंचेगी।

वापसी में यह (26652) 2:20 बजे एनकुलम से रवाना होगी और रात 11 बजे केएसआर बंगलूरु पहुंचेगी। इसके ठहराव कृष्णराजपुरम, जेटीजे-ए, सलेम, इरोड, तिरुपुर, कोयंबटूर, पलक्कड़ और त्रिशूर में होंगे। यह बुधवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी।

फिरोजपुर कैंट-दिल्ली वंदे भारत (26462) बुधवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी। यह सुबह 7:55 बजे फिरोजपुर कैंट से खुलेगी और दोपहर बाद

लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत (26504) सुबह पांच बजे लखनऊ से खुलेगी और दोपहर बाद 12:45 बजे सहारनपुर पहुंचेगी। वापसी की ट्रेन (26503) दोपहर बाद तीन बजे चलकर रात 11 बजे लखनऊ पहुंचेगी। इसका बादा, महोबा और खजुराहो में होगा।

लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत (26504) सुबह पांच बजे लखनऊ से खुलेगी और दोपहर बाद 12:45 बजे सहारनपुर पहुंचेगी। वापसी की ट्रेन (26503) दोपहर बाद तीन बजे चलकर रात 11 बजे लखनऊ पहुंचेगी। इसका बादा, महोबा और खजुराहो में होगा।

2:35 बजे दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 26461 शाम चार बजे दिल्ली से चलकर रात 10:35 बजे फिरोजपुर कैंट पहुंचेगी।

वंदे भारत देश में निर्मित पहली सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन है। इसका निर्माण इंटीग्रेटेड कोच फैक्टरी, चेन्नई में किया जाता है। यह अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है।

इसमें इंटीग्रेजेट ब्रेकिंग सिस्टम, स्वचालित दरवाजे, जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली और बायो वैक्यूम शौचालय जैसे कुछ खास फीचर हैं। एक्सक्लूजिव श्रेणी में रोटेटिंग सीटें लगी हुई हैं। इसकी विशेष ब्रेकिंग प्रणाली 30 प्रतिशत तक बिजली की बचत भी करती है। इसमें लगायी गयी सुविधाओं को दिव्यांगों के अनुकूल बनाया गया है ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो।

संसद का शीतकालीन सत्र एक से 19 दिसम्बर तक चलेगा

*** एनसीआर टुडे, नई दिल्ली ***

संसद का शीतकालीन सत्र एक दिसम्बर से शुरू होगा और 19 दिसम्बर तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी देते हुए लिखा 'राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।' श्री रिजिजू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह रचनात्मक और सार्थक सत्र होगा और हमारे लोकतंत्र को मजबूत कर लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। गौरतलब है कि संसद के मानसून सत्र में बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा तथा आपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराने की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदन का अधिकांश समय बाधित रहा था।

कुपवाड़ा में सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दो आतंकवादियों को मार गिराया

*** वेबवार्ता, श्रीनगर ***

जम्मू-कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दो अज्ञात आतंकवादियों को मार गिराया है। सेना ने शनिवार को यह जानकारी दी। सेना ने बताया कि सतर्क सैनिकों ने कल देर रात नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध गतिविधि देखी और घुसपैठियों को चुनौती दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। घुसपैठियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कार ने एक्स पर कहा, 'चल रहे अभियान में सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया है।' इससे पहले सेना ने कहा था कि सेक्टर में घुसपैठ की संभावित कोशिश के बारे में विशेष खुफिया जानकारी मिलने के बाद सैनिकों ने एक संयुक्त अभियान शुरू किया था। चिनार कार ने कहा, 'सात नवंबर 2025 को घुसपैठ की कोशिश के संबंध में एजेंसियों से मिली विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और उन्हें चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी जिससे मुठभेड़ शुरू हो गयी और आतंकवादियों को घेर लिया गया।'

कांग्रेस का तंज : जी-20 शिखर बैठक में शामिल नहीं होंगे ट्रम्प तो मोदी जाएंगे

*** एनसीआर टुडे, नई दिल्ली ***

कांग्रेस ने जी-20 शिखर बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के शामिल नहीं होने की खबर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब इस बैठक में प्रधानमंत्री के जाने की संभावना है।

जी-20 देशों की शिखर बैठक 22 तथा 23 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में हो रही है। माना जा रहा है कि अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही अनबन के मद्देनजर श्री ट्रम्प इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं।

कांग्रेस संघर्ष विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने श्री मोदी के बैठक में शामिल होने को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर तंज करते हुए लिखा 'अब जब राष्ट्रपति ट्रम्प ने घोषणा की है कि वह 22-23 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में जी20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे, तो हम निश्चित हो सकते हैं कि स्वयंभू विश्वगुरु स्वयं व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे। कभी न कभी, कहीं न कहीं...'

श्री मोदी की यात्रा पर कांग्रेस की यह टिप्पणी उन खबरों के बाद आई है जिनमें कहा जा रहा है कि श्री ट्रम्प इस बैठक का बहिष्कार कर सकते हैं। जी-20 शिखर सम्मेलन आर्थिक और भूराजनीतिक चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर विचार करने का एक प्रमुख वैश्विक मंच है, जिसमें श्री मोदी की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर सबकी नजर रहती है।



गौरतलब है कि श्री मोदी इस महीने की शुरुआत में मलेशिया में क्षेत्रीय नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प उसमें आये थे। कांग्रेस पूत्र कहते हैं कि श्री मोदी जानबूझकर ट्रम्प का सामना करने से बचना चाहते थे इसलिए वह इस सम्मेलन में नहीं गये। उनका यह भी कहना था कि श्री ट्रम्प लगातार दावा कर रहे हैं कि टैरिफ का डर दिखाकर उन्होंने पाकिस्तान के साथ भारत की सैन्य कार्रवाई को रुकवाया था लेकिन श्री मोदी ने संसद में कहा कि किसी बाह्य व्यक्ति या संस्था के दबाव में सैन्य कार्रवाई नहीं रोकी गई।

श्री मोदी के इस बयान के बाद भारत और अमेरिका के बीच रिरते तनावपूर्ण हो गए और आगस्ट में ट्रम्प प्रशासन ने यह कहते हुए भारतीय विचार करने का एक प्रमुख वैश्विक मंच है, जिसमें श्री मोदी की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर सबकी नजर रहती है।

अपने पुराने बैंक खाते में पैसे जमा करके भूल गए?

जो आपका है उसे वापस दिलाने में आरबीआई आपकी मदद करेगा।

आपके बैंक के निष्क्रिय खाते (2 वर्ष से ज्यादा और 10 वर्ष तक असक्रिय) में जमा पैसे / दावा न की गई जमा राशि (10 वर्ष से अधिक) को आरबीआई के डीईए फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप या आपके कानूनी वारिस उसे कभी भी वापस ले सकते हैं।

आपके पैसे वापस पाने के 3 आसान चरण

1. आपके बैंक की किसी भी शाखा में जाएं, भले ही वो आपकी नियमित शाखा न हो।
2. केवाईसी दस्तावेजों (आधार, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस) के साथ फॉर्म जमा करें।
3. सत्यापन के बाद ब्याज समेत, यदि है तो, अपने पैसे वापस पाएं।

आपके दावा न किए गए पैसे के बारे में जानने के लिए

आपके बैंक की वेबसाइट पर खोजें या आरबीआई के UDGM पोर्टल (<https://udgam.rbi.org.in>) पर देखें, जिसमें फ़िलहाल 30 बैंक शामिल हैं।

दावा न की गई संपत्ति के संबंध में आयोजित विशेष शिविरों में जाएं, जिसे देशभर के सभी ज़िलों में अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच लगाए जाएंगे।

आरबीआई कहता है... जानकार बनिए, सतर्क रहिए!

अधिक जानकारी के लिए <https://rbikehtahai.rbi.org.in> देखिए
प्रतिक्रिया के लिए rbikehtahai@rbi.org.in पर लिखिए

आधिकारिक वॉट्सऐप नंबर 99990 41935

जानहित में जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

जलवायु संरक्षण के लिए ब्राजील में भारत ने दोहराई अपनी प्रतिबद्धता

*** एनसीआर टुडे, नई दिल्ली ***

भारत ने जलवायु संरक्षण की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा है कि विकसित देशों को उत्सर्जन में कमी करने के उपाय तेज कर समान कार्रवाई के सिद्धांत को अपनाते अपनी भौगोलिक तथा अन्य परिस्थितियों के अनुरूप जलवायु संरक्षण की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए।

ब्राजील के बेलेम में कॉप-30 देशों के नेताओं के शिखर सम्मेलन में ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया ने समतामूलक जलवायु कार्रवाई के प्रति दुनिया के समक्ष भारती प्रतिबद्धता दोहराई है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन-यूएनएफसीसीसी के 30वें सम्मेलन कॉप-30 का आयोजन 10 से 21 नवंबर तक ब्राजील के बेलेम में आयोजित किया जा रहा है।

श्री भाटिया ने कहा कि भारत ने पेरिस समझौते की 10वीं वर्षगांठ पर कॉप-30 की मेजबानी के लिए ब्राजील का आभार व्यक्त किया और रियो शिखर सम्मेलन की 33 वर्षों की विरासत को याद किया।

भारत के बयान में कहा गया है कि यह ग्लोबल वार्मिंग को चुनौती के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया पर विचार करने तथा रियो शिखर सम्मेलन की विरासत का जश्न मनाने का अवसर है, जहाँ समता और विभेदित उत्तरदायित्वों और संबंधित क्षमताओं-सीबीडीआर-आरसी के सिद्धांतों को अपनाया गया था। इस सिद्धांत ने पेरिस समझौते सहित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु व्यवस्था की नींव रखी। भारत के वक्तव्य में बताया गया है कि 2005 से 2020 के बीच, भारत ने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 36 प्रतिशत कमी की है और यह प्रवृत्ति जारी है।

वक्तव्य में कहा गया है कि गैर-जीवाश्म ऊर्जा अब हमारी स्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक है, जिससे देश संशोधित एनडीसी लक्ष्य को निर्धारित समय से पांच वर्ष पहले प्राप्त कर सकेगा। श्री भाटिया ने कहा कि भारत ने उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए सामूहिक और सतत वैश्विक कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इसे मान्यता देते हुए उष्णकटिबंधीय वनों के लिए संदेव सुविधा स्थापित करने की बाजील की पहल का स्वागत किया और पर्यवेक्षक के रूप में इस सुविधा में शामिल हो गया।



शिखर सम्मेलन की 33 वर्षों की विरासत को याद किया।

भारत के बयान में कहा गया है कि यह ग्लोबल वार्मिंग को चुनौती के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया पर विचार करने तथा रियो शिखर सम्मेलन की विरासत का जश्न मनाने का अवसर है, जहाँ समता और विभेदित उत्तरदायित्वों और संबंधित क्षमताओं-सीबीडीआर-आरसी के सिद्धांतों को अपनाया गया था। इस सिद्धांत ने पेरिस समझौते सहित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु व्यवस्था की नींव रखी। भारत के वक्तव्य में बताया गया है कि 2005 से 2020 के बीच, भारत ने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 36 प्रतिशत

नगीना मे थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया

✳ **एनसीआर टुडे, नगीना** ✳। थाना नगीना में पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉक्टरअंजनी कुमार चतुर्वेदी व नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में कुल शिकायत दर्ज की गई। शिकायतों की सुनवाई नायब तहसीलदार अजब सिंह व क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने सुनी। इस अवसर पर नायब तहसीलदार अजब सिंह कुमार उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह सुभाष तोमर लेखपाल अंरसल हक आदि लेखपाल मौजूद रहे। सवि्त अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

ठगी से बचने के गुर बताए

✳ **एनसीआर टुडे, नोएडा** ✳। मिशन शक्ति अभियान-5.0 के अंतर्गत कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर के थाना क्षेत्रों में शनिवार को महिला सशक्तिकरण एवं महिला सुरक्षा जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान मिशन शक्ति टीम ने महिलाकर्मियों को थानों पर गठित मिशन शक्ति केंद्र के उद्देश्य, कार्य प्रणाली एवं महिला सुरक्षा से संबंधित उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। साइबर ठगी के प्रकार और इससे बचने के उपायों की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं और बच्चियों को विविध हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी बताया गया।

बदमाशों ने सोने की चेन लूटी

✳ **एनसीआर टुडे, नोएडा** ✳। सेक्टर-113 थानाक्षेत्र स्थित रेस्टोरेंट के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति के गले से सोने की चेन लूट ली। पुलिस को दी शिकायत में सेक्टर-77 स्थित इलाइट सोसाइटी निवासी राकेश गुप्ता ने बताया कि बीते माह 25 तारीख को वह थानाक्षेत्र स्थित क ख ग रेस्टोरेंट गए थे। रात नी बजे के करीब जब राकेश रेस्टोरेंट के बगल वाले प्लॉट के पास खड़े थे, तभी एक बाइक पर सवार होकर दो बदमाश आए। पीछे बैठे बदमाश ने राकेश के गले से सोने की चेन झपट ली। बदमाश ने शिकायतकर्ता को धक्का देकर नीचे गिराने का भी प्रयास किया। पीड़ित के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तबतक बदमाश फरार हो चुके थे। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

सड़क पर पैदल जा रही युवती को बेकाबू बस ने कुचला, मौत

✳ **एनसीआर टुडे, नोएडा** ✳। सेक्टर 142 में शनिवार की सुबह एक युवती को बेकाबू बस ने कुचल दिया। हादसे में युवती की मौत हो गई। घटना के वक्त युवती पैदल कंपनी में नौकरी करने जा रही थी। आरोपी चालक बस को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक इकोटेक तीन कोतवाली क्षेत्र के सरस्वती एनक्लेव कॉलोनी में 19 वर्षीय युवती सुजाता परिवार के साथ रहती थीं। युवती नोएडा की एक कंपनी में नौकरी करती थी। शनिवार की सुबह युवती अपनी मां के साथ कंपनी में द्यूटी के लिए पैदल जा रही थी। क्रासा चौराहे के पास पीछे से आ रही बस ने युवती को टक्कर मार दी। घायल युवती को उपचार के लिए नजदीक के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस और युवती के परिजन मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बस को कब्जे में लिया है। पुलिस आरोपी चालक की तलाश में जुटी है। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

पहले बच्चे को पीटा फिर दादा और मां के साथ मारपीट

✳ **एनसीआर टुडे, ग्रेटर नोएडा** ✳। ग्रेटर नोएडा, 08 नवंबर (वेब वार्ता)। बीटा दो कोतवाली क्षेत्र की डिवाइन ग्रेस सोसाइटी में रहने वाले एक परिवार के बच्चे के साथ मारपीट की गई। बच्चे के दादा और मां इसकी शिकायत लेकर आरोपी के घर पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने दंपति समेत छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सोसाइटी में रहने वाली अनीता देवी ने पुलिस को बताया कि एक नवंबर को उसके बेटे का जन्मदिन था। पीड़िता के मुताबिक, उसका 10 वर्षीय बेटा पड़ोस में रहने वाले अपने दोस्तों को जन्मदिन के लिए बुलाने के लिए गया था। इसी बीच पड़ोसी सुभाष के 13 वर्षीय बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला के बेटे के साथ मारपीट की। महिला अपने समुद्र के साथ आरोपी के घर शिकायत करने पहुंची तो आरोपियों ने महिला और उसके समुद्र को भी पीटा। स

फरीदाबाद पहुंची बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा; क्रिकेटर शिखर धवन भी जुड़े

फरीदाबाद, एजेंसी। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 'सनातन हिन्दू एकता पदयात्रा' शनिवार सुबह फरीदाबाद में प्रवेश कर गई। क्रिकेटर शिखर धवन भी इस यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पाली चौक पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। पदयात्रा के दौरान कई सड़कों पर जाम लगने और रूट डायवर्जन के चलते फरीदाबाद से गुरुग्राम जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शुक्रवार 7 नवंबर को शुरु हुई यह पदयात्रा 16 नवंबर को वृंदावन में संपन्न होगी। पदयात्रा के स्वागत के लिए ईएसआईसी चौक से सैनिक कॉलोनी चौक तक लोगों ने यात्रा मार्ग पर स्थित अपने घरों की छतों पर जय श्री राम लिखे झंडे लगाए। पदयात्रा के दौरान पुरे में खड़े पर जगह-जगह भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने यात्रा मार्ग से रोके वाहनों को हटवा दिया। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा आज सुबह जैसे ही हरियाणा के फरीदाबाद जिले में पहुंची, माहील पूरी तरह भक्तिमय हो गया। दिल्ली के छतरपुर से शुरु हुई यह यात्रा आज अरवली के भांगर कट से होते हुए पाली पहुंची। पदयात्रा में बाबा बागेश्वर के साथ क्रिकेटर शिखर धवन भी शामिल हैं। इस बीच मंत्रोच्चार, ढोल-नगाड़ों और जय श्रीराम के नारों से पूरा क्षेत्र गुंज उठा। पाली चौक पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया।

छत्तीसगढ़ में अडानी के प्रोजेक्ट पर भड़का लोगों का गुस्सा बोले- किसी कीमत पर नहीं होने देंगे यह काम

रायगढ़, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित धरमजयगढ़ क्षेत्र में अंबुजा-अडानी की प्रस्तावित परियोजना को लेकर विरोध की लहर थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार 24 घंटे तक रायगढ़ कलेक्ट्रेट के बाहर खुले आसमान के नीचे धरना देने के बाद अब ग्रामीणों ने सीधा एलान कर दिया है कि वे पुरांग में किसी भी कीमत पर जनसुनवाई को नहीं होने देंगे।



बीते दो दिनों से महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की भारी भीड़ कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर डटी रही लेकिन प्रशासन और ग्रामीणों के बीच किसी भी तरह की बातचीत का रास्ता नहीं निकल सका। इस दौरान स्थानीय विधायक उमेश पटेल और लालजीत राठिया भी पूरी रात धरनास्थल पर ग्रामीणों के साथ मौजूद रहे। शुक्रवार सुबह ग्रामीण अपने गांव लौट तो गए लेकिन उन्होंने साफ चेतावनी दी कि धरमजयगढ़ की

जमीन, जंगल और जलस्रोत की सुरक्षा के लिए जनसुनवाई को हर हाल में रोका जाएगा। महिलाओं ने आंदोलन के दौरान कहा, हमारे गांव, हमारे जंगल और पहाड़ बचेंगे, तभी हमारे बच्चे बचेंगे-इसलिए हम यहां खड़े हैं। वहीं, विधायक उमेश पटेल और लालजीत राठिया ने ग्रामीणों के साथ खड़े रहते हुए प्रशासन पर ग्रामीणों की बात न सुनने का आरोप लगाया। लालजीत राठिया ने कहा- दो दिन तक ग्रामीण भूख-प्यासे बैठे रहे, लेकिन

कलेक्टर मिलने तक नहीं आए। अब हम अपनी जमीन और जंगल बचाने गांव लौट रहे हैं, और जनसुनवाई को किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। विधायकों के इस रुख से आंदोलन को और मजबूती मिल गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में विरोध और तीखा हो सकता है। उधर अरुण कलेक्टर और एसडीएम महेश शर्मा भी पारित कर दिया है लेकिन आदिवासी विरोधी भाजपा सरकार पेंसा कानून को ठेगा दिखाते हुए जनसुनवाई को लेकर अड़ी हुई है।

पीओ कंपनी की मिनरल्स बोटल में मरी हुई मकड़ी की वीडियो वायरल

✳ **एनसीआर टुडे, नगीना** ✳

पीओ (PIO) कंपनी की मिनरल्स पानी की 20 रुपये वाली बोटल खरीदने पर बोटल के अंदर मरी हुई मकड़ी सड़ने से रेलवे फाटक के निकट हिंदुरतान कन्फेक्शनरी दुकान पर हंगामा करते हुए राहगीर ग्राहकों ने जान से खिलवाड़ करने के गंभीर आरोप लगाए।



कोतवाली रोड रेलवे फाटक के पास स्थित हिंदुरतान कन्फेक्शनरी दुकान से एक 20 रुपये वाली पीओ (PIO) कंपनी की पानी की बोटल के अंदर मरी हुई मकड़ी सड़ने वाली एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। उधर कन्फेक्शनरी के आस पास के ग्राहकों व लोगों में बोटल के अंदर मरी हुई मकड़ी मिलने से हड़कंप मच गया।



सीधा कंपनी की कमी बताते हुए अपना पीछा छुड़ाया। इस पर मीडियाकर्मियों ने पीओ (PIO) कंपनी के मालिक नगीना मेडिकल के संचालक पवन कटारिया से इस मामले में जानकारी की। तो उन्होंने सीधा ड टोक में कहा कि जिसने यह शिकायत की है। उसे डीएम साहब ने बुलाया है और 7 से 8 बजे रात को ही उसके साथ मीटिंग होगी। तभी हम आपको पूरी जानकारी दे सकेंगे। समाचार भेजे जाने तक इस मामले में शिकायतकर्ता ग्राहक की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई थी।

चुनावी रैली में सिख धार्मिक चित्रों के इस्तेमाल पर बवाल, अनुसूचित जाति आयोग ने जारी किया नोटिस

तरनतारन, एजेंसी। पंजाब में तरनतारन विधानसभा सीट उपचुनाव के दौरान भाई जीवन सिंह (भाई जैता जी) और गुरु तेग बहादुर साहिब की छवियों के अपमानजनक उपयोग का विवाद गहराता जा रहा है। इसी मामले को लेकर पंजाब अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जसबीर सिंह गढ़ी ने पंजाब कांग्रेस को एक और नोटिस जारी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बनवाजा को 10 नवंबर को बुलाया है। तरनतारन के उपायुक्त को आधिकारिक पत्र के जरिए इस संबंध में 17 नवंबर को आयोग के समक्ष पेशा होगा है।



जसबीर सिंह गढ़ी ने बताया कि यह मामला सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से आयोग के संज्ञान में आया है। इस पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने बाजवा को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, तरनतारन के उपायुक्त को एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से इस संबंध में 17 नवंबर तक सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला रिपोर्ट में आदर्श आचार संहिता और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों पर विचार करने के बाद की गई

कार्रवाई शामिल होनी चाहिए। इससे पहले आयोग पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह राजा चडिंग को भी पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह के मामले में तलब कर चुका है। ताजा मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इंटरनेट यूजर्स संयमित भाषा का इस्तेमाल करने की बात कह रहे हैं।

सेक्टर-15 मेट्रो स्टेशन से आईओसीएल तक बनेगा 121 मीटर लंबा स्काई वॉक

✳ **एनसीआर टुडे, नगीना** ✳

सेक्टर-15 मेट्रो स्टेशन से सेक्टर-1 के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) को जोड़ते हुए 121 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा स्काई वॉक बनेगा। इससे सड़क पार करने वालों को राहत मिलेगी। नोएडा प्राधिकरण ने इसका टेंडर निकाला है। इसकी लागत 15.4 करोड़ रुपये होगी।

स्काई वॉक को बीओटी (बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर) के आधार पर बनेगा। जो एजेंसी बनाएगी उसके पास स्काई वॉक पर विज्ञापन लगाने का अधिकार होगा। इससे कंपनी अपनी लागत निकाल सकेगी।

11 साल बाद इसे प्राधिकरण को सौंप देगी। प्राधिकरण के जीएम आरपी सिंह ने बताया कि टेंडर के बाद एजेंसी चुन लिये जाने तक इस स्काई वॉक से आठ माह में तैयार कराया जाएगा। प्राधिकरण को

11 वर्षों में करीब 15 करोड़ के राजस्व की भी प्राप्ति होगी। सेक्टर-15 मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली की ओर से दो राशतों से आने वाले वाहनों का दबाव रहता है। नोएडा के उद्योग मार्ग पर यातायात का भारी दबाव होता है। मेट्रो स्टेशन के नीचे से डीएससी रोड दूसरे स्टेशन को जोड़ता है। ऐसे में पैदल सड़क पार करने में लोगों को दिक्कत होती है। इसके समाधान की मांग कई साल से की जा रही थी।

य्या है-योजना सेक्टर-15 मेट्रो स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों को सीढ़ियों के रास्ते



नीचे मुख्य सड़क पर न उ त र क र स्काई वॉक के सहारे पु लि स आ गे सेक्टर-14 की ओर जाने की

सुविधा मिलेगी। इसकी मदद से लोगों को मुख्य सड़क पर चौराहे और दूसरे अन्य राशतों से आने वाले वाहनों के बीच से सड़क पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

मेट्रो स्टेशन से सेक्टर-14 को जोड़ने वाले स्काई वॉक के बीच में सेक्टर-14 के कोने से एक और स्काई वॉक निकलेगा जो सेक्टर-1 इंडियन ऑयल बिल्डिंग तक जाएगा। उद्योग मार्ग जाने वाले यात्रियों को मेट्रो

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया

कुपवाड़ा , एजेंसी।

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के साथ घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया। साथ ही, जवानों ने 2 अज्ञात आतंकवादियों को मारा गिराया है। सेना के श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने बताया कि खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिला था। इसके आधार पर कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को रोकने के लिए अभियान शुरू किया गया। सेना ने एक्स पर पोस्ट में कहा, सतर्क सैनिकों ने सदिग्ध गतिविधि देखी और चुनौती दी। इस दौरान आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया। फिलहाल इलाके की तलाशी जारी है।



वहीं, श्रीनगर में पुलिस ने शुक्रवार को तीन सदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से हथियार और गोला-बारूद जब्त कर आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ममता चौक, कोनाखान डलगेट के पास नियमित वाहनों की जांच चल रही थी। इस दौरान पुलिस की टीम ने बिना पंजीकरण संख्या वाली काले रंग की मोटरसाइकिल को रोका। रुकने का इशारा करने पर दो मोटरसाइकिल सवार और पीछे बैठे दो लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन सतर्क पुलिसकर्मियों ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया

अजित पवार के बेटे पर लगे जमीन घोटाले के आरोपों के बाद ऐक्शन, डील रद्द

मुंबई, एजेंसी। बेटे पार्थ पवार की विवादास्पद लैंड डील पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। अजित पवार ने कहा कि उनके बेटे पार्थ पवार से कथित तौर पर जुड़ा विवादास्पद भूमि सौदा रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने मामले की जांच रिपोर्ट की भी बात कही है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पुणे भूमि सौदे की जांच कर रही सरकारी समिति एक महीने में रिपोर्ट सौंपेगी।



इससे पहले बेटे से जुड़ी एक कंपनी पर अवैध जमीन सौदे में शामिल होने के आरोप लगने के एक दिन बाद अजित पवार ने, शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। पवार के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी थे। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास 'वर्षा' में हुई यह मुलाकात लगभग 30 मिनट तक चली।

गौरतलब है कि अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार से जुड़ी

एक कंपनी द्वारा किए गए 300 करोड़ रुपये की लागत से 40 एकड़ जमीन की खरीद के सौदे में गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। इसके चलते अब यह सौदा जांच के दायरे में आ गया है। सरकार ने गुरुवार को एक उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दिए, मामले में शामिल एक उप-पंजीयक को निर्लंबित कर दिया और तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की। वहीं, महाराष्ट्र में 300 करोड़ रुपये के भूमि सौदे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे के व्यावसायिक साझेदार दिग्विजय पाटिल समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने के एक दिन बाद शुक्रवार को पाटिल, शीतल तेजवानी और निर्लंबित राजस्व अधिकारी सूर्यकांत येवाले के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की गई।

यूपी में पशु तस्करो के खिलाफ बड़ा अभियान, आधी रात को फिर हुआ एनकाउंटर

देवरिया, एजेंसी। उत्तर प्रदेश में पशु तस्करो के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चला रखा है। इसके तहत शुक्रवार की आधी रात को फिर एनकाउंटर हुआ है। इस बार प्रदेश के देवरिया जिले में पुलिस और पशु तस्करो के बीच गोलियां तड़तड़ाईं। इसमें पैर एक पशु तस्करो को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया। उसे इलाज के लिए देवरिया के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बता दें कि एक दिन पहले ही लखनऊ एसटीएफ और आजमगढ़ पुलिस के ज्वाइट ऑपरेशन में 50 हजार रुपये के इनामी पशु तस्करो को एनकाउंटर में मार गिराया गया था। मारे गए बदमाश की पहचान 27 साल के वाकिब उर्फ वाकिफ के रूप में हुई थी। वह आजमगढ़ के फूलपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। देवरिया में पकड़े गए पशु तस्करो का नाम मुबारक है।

वह पड़ोसी राज्य बिहार के सिवान जनपद के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम हरिहास का रहने वाला है। मुबारक के खिलाफ 2023 में पशु तस्करी का केस दर्ज किया गया था। वह इस मामले में फरार चल रहा था। आधी रात के बाद पुलिस को सूचना मिली कि वह खरबनिया बंधे के पास है और मोटर साइकिल से जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस पहुंच गई और घेराबंदी की।



संपादकीय

आम आदमी को अदालतों से सस्ता सुलभ न्याय कब मिलेगा?

देश की अदालतों से आम आदमी को इंसाफ मिलना आज भी सपना बना है। जटिल न्यायिक प्रक्रिया अदालत में ऊपर से नीचे तक हर पायदान पर व्याप्त भ्रष्टाचार और मुकदमों के अनुपात में न्यायिक अधिकारियों का अभाव इसका जिम्मेदार है।

कुछ लोग तो जीवन भर न्याय पाये की चाहत में दम तोड़ जाते हैं लेकिन अदालत से फैसला नहीं मिलता। समय पर न्याय, न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास की आधारशिला है, जैसा कि इस कहावत में भी स्पष्ट है कि 'न्याय में देरी, न्यायतंत्र से इनकार के समान है।' लंबे समय तक देरी अक्सर लोक को अदालत जाने से रोकती है। पिछले साल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस द्विद्वक को 'ब्लैक कोर्ट सिंड्रोम' कहा था। लेकिन अब इसका दायरा चौकाने वाला है। सर्वोच्च न्यायालय में 86, 700 से ज्यादा मामले, उच्च न्यायालयों में 63.3 लाख से ज्यादा मामले और जिला व अधीमस्थ न्यायालयों में 4.6 करोड़ मामले लंबित हैं। कुल मिलाकर, भारत में लंबित मामलों की कुल संख्या 5 करोड़ से ज्यादा है।

हाल ही में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा को बताया था कि भारत भर की विभिन्न निचली अदालतों में 4.6 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। यह बेहद शर्मनाक स्थिति है जबकि मौजूदा सरकार ने देश भर में समयबद्ध न्याय देने का वादा किया था लेकिन स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है वरन लंबित मामलों की तादाद जस की तस बनी है। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सांसद कनिमोझी एनवीएन सोमू द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में 86, 723 मामले लंबित हैं, जबकि भारत भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 63, 29, 222 मामले लंबित हैं। "उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 30 जून 2025 तक 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 865 फास्ट ट्रेक कोर्ट कार्यरत हैं।" फास्ट ट्रेक कोर्ट ने अब तक 76, 57, 175 मामलों का निपटारा किया है, जबकि 14, 38, 198 मामले अभी भी उनके पास लंबित हैं। ग्राम न्यायालय (जीएन) पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 200 सितंबर 2020 से जून 2025 तक की अवधि में ग्राम न्यायालयों में 5, 39, 200 मामले दर्ज किए गए। इसी अवधि में ग्राम न्यायालयों ने 4, 11, 071 मामलों का निपटारा किया। 30 जून 2025 तक, ग्राम न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 1, 28, 129 है। "

गोटे तौर पर भारत की अदालतों में 6000 से अधिक जजों की कमी है जिनमें से 5000 जजों की कमी निचली अदालतों में है। 'डिपार्टमेंट आफ जस्टिस' की 1 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार देश के हाईकोर्टों में जजों की स्वीकृत संख्या 1122 के मुक़ाबले में वहां 751 पदों पर ही नियुक्तियां हुई हैं तथा 371 जजों के पद खाली हैं। देश की जनसंख्या 1.4 अरब है और जजों की कुल संख्या सिर्फ 21, 285 है। देश की अदालतों में इस समय 4 करोड़ 66 लाख 24 हजार केस लंबित हैं। इनमें से 3 करोड़ 55 लाख 67 हजार क्रिमिनल तथा 1 करोड़ 10 लाख 57 हजार सिविल केस हैं।

2025 की 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' के अनुसार भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जज हैं जबकि 1987 की 'कानून आयोग' की सिफारिश के अनुसार कम से कम 50 जज होने चाहिए। इसी कारण अदालतों में कार्यरत जजों पर मुकदमों का भारी बोझ पड़ा हुआ है। इसी रिपोर्ट में यह रहस्योद्घाटन भी किया गया है कि देश की जिला अदालतों में एक जज के पास औसतन 2, 200 मुकदमे हैं, वहीं झंझाबाद और मध्य प्रदेश के हाईकोर्टों में प्रत्येक जज के पास 15, 000 तक केस हैं। विधि और संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 24 जुलाई को राज्यसभा में बताया कि हाईकोर्टों में खाली पड़ी 371 रिक्तियों में से 178 पदों के लिए नियुक्ति प्रस्ताव सरकार और हाईकोर्ट की कोलेजियम के बीच विभिन्न चरणों पर विचाराधीन हैं तथा 193 पदों के लिए अभी तक संबंधित हाईकोर्टों की कोलेजियम से सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं।

ऊपर से लेकर नीचे तक देश की अदालतों में जजों की कमी का अदालतों में चल रहे मुकदमों पर पड़ रहे दुष्प्रभाव का अनुमान पिछले 4 महीनों के उदाहरणों से बखूबी लगाया जा सकता है। 20 मार्च, 2025 को राजस्थान में लगभग 40 वर्ष पूर्व हुए एक नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में सुप्रीमकोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दोषी को बरी करने के फैसले को पलटते हुए उसे निचली अदालत द्वारा दी गई 7 वर्ष कैद की सजा को बहाल करने के साथ ही 4 सप्ताह में सरेट्ट करके न्याय आदेश दिया। जजों ने कहा कि बच्ची की चुप्पी का मतलब यह नहीं लगाया जा सकता कि उसके साथ अपराध हुआ ही नहीं।

यह बहुत दुख की बात है कि इस नाबालिग लड़की और उसके परिवार को अपने जीवन के इस भयानक अध्याय को बंद करने के इंतजार में लगभग 40 वर्ष बिताने पड़े। * 30 जून, 2025 को रांची (झारखंड) में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने वर्ष 2005 में 2750 रुपए रिश्वत लेने के 20 वर्ष पुराने मामले में दोषी 'जयराम चौधरी' को 5 वर्ष कैद और 6000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

जुमाना अदा न करने पर उसे 2 महीनों की और सजा काटनी होगी* 21 जुलाई, 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 वर्ष पुराने वर्ष 2006 के मुद्देबंद 187 बल धमकों के सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। इन धमकों में 187 लोग मारे गए तथा 800 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस फैसले पर 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 21 जुलाई, 2025 को ही हरदोई (उत्तर प्रदेश) में 16 दिसम्बर, 2014 को हुए हत्याकांड के 11 वर्ष पुराने मामले में 2 भाइयों को दोषी करार देते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाने के अलावा 20-20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जिला न्यायालयों में दिवानी मामलों में सबसे अधिक दरें होती हैं, जिससे मुकदमों के भार और क्षमता के बीच भारी असंतुलन उत्पन्न होता है।

इन हालातों में जरूरी है कि अदालतों में लटकती आ रही जजों की कमी जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि पीड़ितों को समय रहते न्याय मिल सके और वे न्याय के इंतजार में ही इस संसार से ही न चले जाएं। ऐसे हालात में आम आदमी में कानून और अदालत के प्रति विश्वास कम हो रहा है।

ललित गर्ग

विश्व अर्थव्यवस्था पर किए गए हालिया अध्ययन विशेषकर जी-20 पैनल की रिपोर्ट में एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि धन और संपत्ति के वितरण में असमानता अब चरम पर पहुंच चुकी है।

रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त प्रतिशत की नई बनी संपत्तियों का लगभग आठ प्रतिशत हिस्सा मात्र एक प्रतिशत अमीर लोगों के पास है जबकि निचले पचास प्रतिशत गरीब लोगों के हिस्से में केवल एक प्रतिशत संपत्ति आई है। यह असमानता केवल आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक, सामाजिक और मानवीय संकट का भी संकेत है। यह स्थिति एक आदर्श विश्व संरचना के लिये भी बड़ी बाधा है।

यह ऐसी त्रासद, विद्रोहपूर्ण एवं विडम्बनापूर्ण स्थिति है जिसमें एक तरफ लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में सड़कों पर उतर रहे हैं तो दूसरी ओर अमीर से और अमीर होते लोगों की विलासिता के किस्से तमाम हैं। उदारीकरण व वैश्वीकरण के दौर के बाद पूरी दुनिया में आर्थिक असमानता रूढ़ी का नाम नहीं ले रही है, इससे एक बड़ी आबादी में विद्रोह एवं क्रान्ति के स्वर उभर रहे हैं।

स- 2000 से 2024 के बीच विश्व अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, तकनीकी विकास हुआ, उत्पादन बढ़ा और वैश्वीकरण के नाम पर बाजारों का विस्तार हुआ, लेकिन इस विकास का लाभ समान रूप से नहीं बंटा। अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब।

सन 2000 में जहां विश्व की कुल संपत्ति का पैतलीस प्रतिशत हिस्सा शीर्ष एक प्रतिशत लोगों के पास था, वहीं 2024 तक यह बढ़कर तिरसठ प्रतिशत से भी ऊपर पहुंच गया। इसी अवधि में आधी से अधिक आबादी के हिस्से की संपत्ति घटकर केवल एक प्रतिशत रह गई। यह आंकड़े केवल संख्या नहीं, मानवता की दिशा के संकेत हैं कि हम प्रगति के नाम पर असंतुलन का साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। जो विद्रोह का कारण बन रहा है, हिंसा एवं अराजक का भी कारण बन रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय में फिर से मंडरा रहा है बैंच हंटिंग का डर

के रवींद्र

मुख्य न्यायाधीश का आक्रोश एक आंतरिक दुविधा की भी दशाता है। वह है राजनीतिक टकराव की स्थिति में आए बिना संस्था को सूक्ष्म घुसपैठ से कैसे बचाया जाए। न्यायापालिका को सरकार के साथ खुले टकराव में उतरे बिना अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सावधानी से कदम उठाने चाहिए। लेकिन चुप्पी की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जब पीठों को स्थानांतरित करने या उनका विस्तार करने के प्रयासों को चुनौती नहीं दी जाती।

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई द्वारा केंद्र सरकार को 'बैंच हंटिंग' के प्रयास के लिए कड़ी फटकार लगाने से न्यायिक स्वतंत्रता और भारत के शीर्ष न्यायालय पर कार्यपालिका के प्रभाव को लेकर एक पुरानी और असहज बहस फिर से शुरू हो गई है। इसकी तात्कालिक वजह सरकार की वह मांग थी जिसमें उसने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के अंतिम चरण में पहुंच चुके एक मामले को पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ को स्थानांतरित करने की मांग की थी।

समय और योजना के मद्देनजर यह कदम मुख्य न्यायाधीश को अपनी पीठ के फैसले से बचने की कोशिश के रूप में प्रतीत हुआ, जिसने उस प्रवृत्ति को और पुष्ट किया जो वर्षों से न्यायालय को परेशान करती रही है। वह है शक्तिशाली वादियों द्वारा न्यायपालिका को प्रभावित करने का प्रयास कि नौन से न्यायाधीश किस मामले की सुनवाई करेंगे।

बैंच हंटिंग, एक ऐसी प्रथा रही है जो जितनी सूक्ष्म है उतनी ही विनाशकारी भी। यह न्याय के इस मूल सिद्धांत को कमजोर करती है कि अनूले को सत्ता के प्रति 'अंधा' होना चाहिए। अपने सबसे निंदनीय रूप में, यह असुविधाजनक या स्वतंत्र विचारों वाली समझी

जी-20 पैनल के अध्ययन के अनुसार, वर्तमान में वैश्विक श्रत पर असमानता भयावह शतर तक जा पहुंची है। निस्संदेह, भारत भी इस स्थिति में अपवाद नहीं है। देश के सबसे अमीर एक फीसदी लोगों ने केवल दो दशक में अपनी संपत्ति के वितरण में असमानता अब चरम पर पहुंच चुकी है।

रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त प्रतिशत की नई बनी संपत्तियों का लगभग आठ प्रतिशत हिस्सा मात्र एक प्रतिशत अमीर लोगों के पास है जबकि निचले पचास प्रतिशत गरीब लोगों के हिस्से में केवल एक प्रतिशत संपत्ति आई है। यह असमानता केवल आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक, सामाजिक और मानवीय संकट का भी संकेत है। यह स्थिति एक आदर्श विश्व संरचना के लिये भी बड़ी बाधा है।

यह ऐसी त्रासद, विद्रोहपूर्ण एवं विडम्बनापूर्ण स्थिति है जिसमें एक तरफ लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में सड़कों पर उतर रहे हैं तो दूसरी ओर अमीर से और अमीर होते लोगों की विलासिता के किस्से तमाम हैं। उदारीकरण व वैश्वीकरण के दौर के बाद पूरी दुनिया में आर्थिक असमानता रूढ़ी का नाम नहीं ले रही है, इससे एक बड़ी आबादी में विद्रोह एवं क्रान्ति के स्वर उभर रहे हैं।

स- 2000 से 2024 के बीच विश्व अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, तकनीकी विकास हुआ, उत्पादन बढ़ा और वैश्वीकरण के नाम पर बाजारों का विस्तार हुआ, लेकिन इस विकास का लाभ समान रूप से नहीं बंटा। अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब।

सन 2000 में जहां विश्व की कुल संपत्ति का पैतलीस प्रतिशत हिस्सा शीर्ष एक प्रतिशत लोगों के पास था, वहीं 2024 तक यह बढ़कर तिरसठ प्रतिशत से भी ऊपर पहुंच गया। इसी अवधि में आधी से अधिक आबादी के हिस्से की संपत्ति घटकर केवल एक प्रतिशत रह गई। यह आंकड़े केवल संख्या नहीं, मानवता की दिशा के संकेत हैं कि हम प्रगति के नाम पर असंतुलन का साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। जो विद्रोह का कारण बन रहा है, हिंसा एवं अराजक का भी कारण बन रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय में फिर से मंडरा रहा है बैंच हंटिंग का डर

जाने वाली बेंचों को दरकिनार करने और कारंबाई को उन बेंचों की ओर मोड़ने का प्रयास करती है जो अधिक अनुकूल समझी जाती हैं। हालांकि अदालत के गलियारों में इस बारे में लंबे समय से चर्चा होती रही है, न्यायमूर्ति गवई की टिप्पणी ने इस मामले को फिर से खुलकर सामने ला दिया है। इस बार इसके पीछे मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय का जोर है। उनके शब्द न केवल प्रक्रियात्मक पैतरेबाजी से बल्कि एक बार-बार होने वाले पैटर्न से भी निराशा दशाते हैं जो न्यायपालिका की संस्थागत विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करता है।

इस आदान-प्रदान का संदर्भ महत्वपूर्ण है। विचाराधीन मामला न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम की संवैधानिक वैधता से संबंधित है, एक ऐसा कानून जिसकी अर्ध-न्यायिक निकायों में नियुक्तियों और सेवा शर्तों पर कार्यपालिका को व्यापक अधिकार देने के लिए आलोचना की जाती है।

पीठ इस मामले की गहन जांच कर रही है, और याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी दलीलें पूरी करने के बाद सरकार के अनुरोध के समय ने लोगों को चौंका दिया। मुख्य न्यायाधीश को यह एक ऐसे नतीजे को पटरी से उतारने या विलंबित करने का प्रयास लगा जो शायद सरकार को पसंद न हो। इसलिए, उनकी प्रतिक्रिया न केवल न्यायिक स्वायत्तता का बचाव थी, बल्कि उन सीमाओं की भी याद दिलाती थी जो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करती हैं।

यह पहलू परना नहीं है जब इस तरह की चिंताएं सार्वजनिक हुई हैं। इस मुद्दे ने पहली बार जनवरी 2018 में राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया था जब सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों- न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी. लोकरु और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ - ने

आबादी को बाहर वालों से बदलने की साजिश को रोकना जा सके। इस कार्य को करने के लिए दो दिनों का वाइब्रेट क्लिये प्रोग्राम वर्कशॉप कलिया गया। इसमें गृह मंत्री ने जिला कलेक्टरों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने जिलों में सीमा से 30 किलोमीटर तक के अवैध धार्मिक ढांचों को हटा दें। ऐसा करना प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप होगा।

यह रणनीतिक कदम समस्या खड़ी होने से पहले ही उठा लिया जाए। जीवंत गांव कार्यक्रम यानी वाइब्रेट क्लिये प्रोग्राम तीन बिंदुओं पर आधारित है। पहला तो यह है कि सीमावर्ती राज्यों से स्थानीय पलायन रोकना जाए। उत्तराखंड में यह स्थिति बहुत ज्यादा देखने में आ रही है। दूसरी बात यह है कि सीमावर्ती राज्यों के निवासियों को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का शत-प्रतिशत लाभ मिले। तीसरा यह है कि इस प्रोग्राम के तहत सीमा और उसकी सुरक्षा को और मजबूत करने के उपाय किए जाएं। इस कार्यक्रम के तहत पहले से चिन्हित गांवों को जल्दी ही राष्ट्रीय और सीमा सुरक्षा के केन्द्र में

आबादी को बाहर वालों से बदलने की साजिश को रोकना जा सके। इस कार्य को करने के लिए दो दिनों का वाइब्रेट क्लिये प्रोग्राम वर्कशॉप कलिया गया। इसमें गृह मंत्री ने जिला कलेक्टरों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने जिलों में सीमा से 30 किलोमीटर तक के अवैध धार्मिक ढांचों को हटा दें। ऐसा करना प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप होगा।

यह रणनीतिक कदम समस्या खड़ी होने से पहले ही उठा लिया जाए। जीवंत गांव कार्यक्रम यानी वाइब्रेट क्लिये प्रोग्राम तीन बिंदुओं पर आधारित है। पहला तो यह है कि सीमावर्ती राज्यों से स्थानीय पलायन रोकना जाए। उत्तराखंड में यह स्थिति बहुत ज्यादा देखने में आ रही है। दूसरी बात यह है कि सीमावर्ती राज्यों के निवासियों को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का शत-प्रतिशत लाभ मिले। तीसरा यह है कि इस प्रोग्राम के तहत सीमा और उसकी सुरक्षा को और मजबूत करने के उपाय किए जाएं। इस कार्यक्रम के तहत पहले से चिन्हित गांवों को जल्दी ही राष्ट्रीय और सीमा सुरक्षा के केन्द्र में



को दलदल से बाहर निकालने में सफल रहा है। मोदी सरकार के जन-केंद्रित विकास और सामुदायिक भागीदारी के लाभों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। निस्संदेह, इस पहल ने करोड़ों अत्यंत गरीब परिवारों को भोजन, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका के बेहतर साधनों तक पहुंचने में मदद की है।

फिर भी देश में धन-संपत्ति की असमानता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि असंतोष और हिंसा की जड़ है। जब परिश्रमी व्यक्ति को उसका उचित मूल्य नहीं मिलता, जब समाज में अवसर और सम्मान का समान वितरण नहीं होता, तब भीतर आक्रोश और विद्रोह जन्म लेता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने कहा है कि जब पूंजी की आय दर आर्थिक वृद्धि दर से अधिक हो जाती है, तब समाज में असमानता बढ़ती है और लोकतंत्र की जड़ें हिल जाती हैं। आज यही हो रहा है। आर्थिक असंतुलन से सामाजिक असंतुलन उभर रहा है, अविश्वास और द्वेष का वातावरण बन रहा है।

करोना महामारी ने इस असमानता को और गहरा किया। जब करोड़ों लोग बेरोजगार और निर्धन हो गए, तब कुछ गिने-चुने उद्योगपतियों

को दलदल से बाहर निकालने में सफल रहा है। मोदी सरकार के जन-केंद्रित विकास और सामुदायिक भागीदारी के लाभों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। निस्संदेह, इस पहल ने करोड़ों अत्यंत गरीब परिवारों को भोजन, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका के बेहतर साधनों तक पहुंचने में मदद की है।

फिर भी देश में धन-संपत्ति की असमानता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि असंतोष और हिंसा की जड़ है। जब परिश्रमी व्यक्ति को उसका उचित मूल्य नहीं मिलता, जब समाज में अवसर और सम्मान का समान वितरण नहीं होता, तब भीतर आक्रोश और विद्रोह जन्म लेता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने कहा है कि जब पूंजी की आय दर आर्थिक वृद्धि दर से अधिक हो जाती है, तब समाज में असमानता बढ़ती है और लोकतंत्र की जड़ें हिल जाती हैं। आज यही हो रहा है। आर्थिक असंतुलन से सामाजिक असंतुलन उभर रहा है, अविश्वास और द्वेष का वातावरण बन रहा है।

करोना महामारी ने इस असमानता को और गहरा किया। जब करोड़ों लोग बेरोजगार और निर्धन हो गए, तब कुछ गिने-चुने उद्योगपतियों

की संरचना को प्रभावित करने का प्रयास न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भीतर से ही नष्ट करना है। ऐसा हर कदम सार्वजनिक जीवन में न्यायालय के अधिकार को बनाए रखने वाली तटस्थता की धारणा को कमजोर करता है। भले ही कोई औपचारिक कदमाचार सिद्ध न हो, लेकिन हेरफेर का आभास मात्र न्याय प्रणाली में विश्वास को नुकसान पहुंचा सकता है।

न्यायाधीशों को राजनीतिक या संस्थागत प्रभाव से मुक्त रखने का सिद्धांत लोकतांत्रिक वैधता के मूल में है। जब वादी, विशेष रूप से राज्य की शक्ति का प्रयोग करने वाले, अपने पसंदीदा परिणामों के अनुरूप प्रक्रियात्मक कदम उठाते देखे जाते हैं, तो यह इस बारे में संदेह पैदा करता है कि क्या न्यायालय वास्तव में कार्यपालिका की अतिरिक्त पर अंकुश लगाते हैं। इसलिए न्यायमूर्ति गवई की यह स्पष्ट टिप्पणी कि सरकार 'उनकी पीठ से बचने के लिए उत्सुक' प्रतीत होती है, कोई आकरिस्मिक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि एक सार्वजनिक संकेत था कि इस तरह के आचरण को अनदेखा नहीं किया जाएगा। इससे यह संकेत मिलता है कि दुविधा को भी दशाता है।

वह है राजनीतिक टकराव की स्थिति में आए बिना संस्था की सूक्ष्म घुसपैठ से कैसे बचाया जाए। न्यायपालिका को सरकार के साथ खुले टकराव में उतारे बिना अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सावधानी से कदम उठाने चाहिए। लेकिन चुप्पी की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जब पीठों को स्थानांतरित करने या उनका विस्तार करने के प्रयासों को चुनौती नहीं दी जाती, तो वे एक ऐसी संस्कृति को सामंन्य बना सकते हैं जहां शक्तिशाली वादी यह मान लेते हैं कि वे न्यायिक प्रक्रिया को अपने फायदे के लिए बहाल सकते हैं। इस प्रथा का सार्वजनिक रूप से विरोध करके, न्यायमूर्ति गवई ने इस सामान्यीकरण को बर्दाश्त करने से इनकार करने का संकेत दिया है।

पिछले एक दशक में, कई उच्च-दांव वाले संवैधानिक मामलों- चुनावी बांड-योजना को चुनौती देने से लेकर स्थानीय नियुक्तियों से जुड़े विवाद करके, न्यायमूर्ति गवई ने इस सामान्यीकरण को बर्दाश्त करने से इनकार करने का संकेत दिया है।

पिछले एक दशक में, कई उच्च-दांव वाले संवैधानिक मामलों- चुनावी बांड-योजना को चुनौती देने से लेकर स्थानीय नियुक्तियों से जुड़े विवाद करके, न्यायमूर्ति गवई ने इस सामान्यीकरण को बर्दाश्त करने से इनकार करने का संकेत दिया है।

पिछले एक दशक में, कई उच्च-दांव वाले संवैधानिक मामलों- चुनावी बांड-योजना को चुनौती देने से लेकर स्थानीय नियुक्तियों से जुड़े विवाद करके, न्यायमूर्ति गवई ने इस सामान्यीकरण को बर्दाश्त करने से इनकार करने का संकेत दिया है।

पिछले एक दशक में, कई उच्च-दांव वाले संवैधानिक मामलों- चुनावी बांड-योजना को चुनौती देने से लेकर स्थानीय नियुक्तियों से जुड़े विवाद करके, न्यायमूर्ति गवई ने इस सामान्यीकरण को बर्दाश्त करने से इनकार करने का संकेत दिया है।

पिछले एक दशक में, कई उच्च-दांव वाले संवैधानिक मामलों- चुनावी बांड-योजना को चुनौती देने से लेकर स्थानीय नियुक्तियों से जुड़े विवाद करके, न्यायमूर्ति गवई ने इस सामान्यीकरण को बर्दाश्त करने से इनकार करने का संकेत दिया है।

पिछले एक दशक में, कई उच्च-दांव वाले संवैधानिक मामलों- चुनावी बांड-योजना को चुनौती देने से लेकर स्थानीय नियुक्तियों से जुड़े विवाद करके, न्यायमूर्ति गवई ने इस सामान्यीकरण को बर्दाश्त करने से इनकार करने का संकेत दिया है।

पिछले एक दशक में, कई उच्च-दांव वाले संवैधानिक मामलों- चुनावी बांड-योजना को चुनौती देने से लेकर स्थानीय नियुक्तियों से जुड़े विवाद करके, न्यायमूर्ति गवई ने इस सामान्यीकरण को बर्दाश्त करने से इनकार करने का संकेत दिया है।

नजर आना चाहिए, आम जीवनशतर उन्नत होता हुआ भी दिखना चाहिए।

हालांकि, अर्थशास्त्री आमतौर पर संपत्ति कर लगाने के पक्षधर नहीं होते हैं, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अति-धनी लोग सरकारी खजाने में अपना उचित योगदान दें। अब चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सबका ध्यान विकास पर केंद्रित किया जाना चाहिए। तभी देश उत्पादकता के क्षेत्र में आगे बढ़कर गरीबी उन्मूलन की दिशा में सार्थक प्रगति क सकता है। यह पहल ही नये भारत, विकसित भारत के सपने को साकार करने में मददगा साबित हो सकती है।

गरीबी-अमीरी के असंतुलन की स्थिति से निकलने का एक ही मार्ग है-धन का न्यायपूर्ण पुनर्वितरण, समान अवसर और समाजोपयोगी नीति। कर व्ययस्था ऐसी हो जो अमीरों से अधिक कर लेकर गरीबों की शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन शतर को सुदृढ़ करे।

अवसरों की समानता तभी संभव है जब शिक्षा और स्वास्थ्य सभी के लिए समान रूप से सुलभ हों। लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है ताकि नीति पूंजी के लिए नहीं, नागरिक के लिए बने। परंतु केवल नीतियों से नहीं, दृष्टि से परिवर्तन आएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था-"गरीब पापी नहीं, जीवित देवता है।"

उनकी सेवा ही ईश्वर की सेवा है।" दूसरी बड़ी बात है कि जब कुछ लोग सब कुछ पा लेते हैं, तो बाकी सब कुछ खो देते हैं। इसलिए सरकारें वोट बैंक की राजनीति से इतर ईमानदारी से पहल करें तो गरीबी उन्मूलन की दिशा में सार्थक, समता एवं सतुलन के दृश्य स्थापित किये जा सकते हैं।

चुनाव से पहले मुफ्त की रेवडुडियां बांटने की तेजी से बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। यह एक हकीकत है कि कोई भी सुविधा मुफ्त नहीं हो सकती। इस तरह की लोकलुभावनी कोशिशों से राज्यों का वित्तीय घाटा ही प्रभावित होता है। जिसकी कीमत लोगों को विकास योजनाओं से दूर रहकर ही चुकानी पड़ती है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती आशा शर्मा द्वारा 707 मंदाकिनी टावर सेक्टर -4, वैशाली गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) भारत से प्रकाशित एवं एन.सी.आर. प्रिंटेर्स, 15/19 साइट-4, साहिबाबाद इंडस्ट्रीयल एरिया जनपद गाजियाबाद से मुद्रित। संपादक : संजय शर्मा

फ़ोन: 9899683800

वेबसाइट : www.khabariya.com

ई-मेल: todayncr@gmail.com

>>> ncrtoday@hotmail.com

RNI-UPHIN/2009/30721

राहुल वी एस भारत के 91वें ग्रैंडमास्टर बने, आसियान व्यक्तिगत चैंपियनशिप में हासिल की उपलब्धि

नई दिल्ली, एजेंसी। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (एआईसीएफ) के अध्यक्ष नितिन नारंग ने एक्स पर लिखा, राहुल वी एस को एक राउंड शेष रहते आसियान व्यक्तिगत चैंपियनशिप जीतने और इस प्रक्रिया में देश के 91वें ग्रैंडमास्टर बनने पर हार्दिक बधाई। भारतीय शतरंज खिलाड़ी राहुल वीएस छठी आसियान व्यक्तिगत चैंपियनशिप को एक राउंड शेष रहते हुए जीतकर देश के 91वें ग्रैंडमास्टर बन गये हैं। यह 21 वर्षीय खिलाड़ी एशियाई जूनियर चैंपियन भी है। वह 2021 में अंतरराष्ट्रीय मास्टर बने थे। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (एआईसीएफ) के अध्यक्ष नितिन नारंग ने एक्स पर लिखा, राहुल वी एस को एक राउंड शेष रहते आसियान व्यक्तिगत चैंपियनशिप जीतने और इस प्रक्रिया में देश के 91वें ग्रैंडमास्टर बनने पर हार्दिक बधाई। आपको आगे भी कई उपलब्धियां हासिल करने और भारत को गौरवान्वित करने में निरंतर सफलता हासिल करने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। फिलीपीन्स में आसियान व्यक्तिगत चैंपियनशिप में राहुल ने जीत हासिल करके अपना अंतिम ग्रैंडमास्टर नॉर्म हासिल किया। वह पिछले दो सप्ताह के अंदर ग्रैंडमास्टर बनने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। उनसे पहले युवा खिलाड़ी इलमपथी ए आर ने 30 अक्टूबर को यह उपलब्धि हासिल की थी।



अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास...



पूरे किए हजार टी20 रन, सूर्या कारिकॉर्ड ध्वस्त

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला 8 नवंबर (रविवार) को ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेला है। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यानी भारतीय टीम को इस मैच में पहले बैटिंग करनी पड़ी। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम को इस मुकाबले में शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने तुफानी शुरुआत दिलाई। इस दौरान बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक ने टी20 इंटरनेशनल (टी20इ) में बेहद खास उपलब्धि भी हासिल की। अभिषेक ने टी20 इंटरनेशनल में अपने 1000 हजार रन पूरे कर लिए। देखा जाए तो अभिषेक शर्मा गेंदों के हिसाब से टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज हजार रन बनाने वाले बैटर (फुल मेम्बर्स टीम) बन गए हैं। अभिषेक ने एक हजार रन बनाने के लिए 528 गेंदें ली हैं। अभिषेक ने भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सूर्यकुमार ने एक हजार रन बनाने के लिए 573 गेंदें ली थीं। यहीं नहीं अभिषेक इनिंग्स के हिसाब से दूसरे सबसे

तेज हजार टी20इ रन बनाने वाले भारतीय हैं। गेंदों के हिसाब से सबसे तेज 1000 टी20 रन (फुल मेम्बर्स टीम) 528- अभिषेक शर्मा (भारत) 573- सूर्यकुमार यादव (भारत) 599- फिल साल्ट (इंग्लैंड) 604- खेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया) 609- आंद्रे रसेल (वेस्टइंडीज)/फिन एलन (न्यूजीलैंड) सबसे कम पारियों में हजार टी20 रन (भारत) 27- विगत कोहली 28- अभिषेक शर्मा 29- केएल राहुल 31- सूर्यकुमार यादव 40- रोहित शर्मा गाबा टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा को दो जीवनदान भी मिले हैं। पहले ही ओवर में वेन इवारशुस की गेंद पर खेन मैक्सवेल ने अभिषेक शर्मा का मिड-ऑफ रीजन में कैच टपका दिया।

हांग कांग इंटरनेशनल सिक्सेस 2025 में टीम इंडिया की लगातार तीन हार, कुवैत, यूएई और नेपाल तक से मिली हार

हांग-कांग, एजेंसी। हांग कांग इंटरनेशनल सिक्सेस 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करने वाली दिनेश कार्तिक की अगुवाई वाली टीम को लगातार तीन करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते वे क्वार्टर फाइनल की दौड़ से बाहर हो गए हैं। कुवैत, यूएई और नेपाल ने भारत को बुरी तरह शिकस्त दी।

यूएई से हार गए, अभिमन्यु मिथुन (50) और दिनेश कार्तिक (42) की तुफानी पारियों की बदेलात भारत ने 108 रन बनाए थे, लेकिन यूएई के खालिद शाह ने सिर्फ 14 गेंदों में 50 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया और भारत को फिर हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद नेपाल से शर्मनाक हार मिली, दिन का आखिरी मैच भारत के लिए सबसे बुरा साबित हुआ। नेपाल ने बिना कोई विकेट खोए 6 अक्टूबर में 137 रन का विशाल

इंडिया-ए वर्सेस साउथ अफ्रीका: ध्रुव जुरेल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार दूसरी पारी में लगाया शतक, मजबूत स्थिति में इंडिया



नई दिल्ली, एजेंसी। इंडिया ए के विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ कमाल की बल्लेबाजी करते हुए दूसरी पारी में भी शतक लगा दिया। ध्रुव पहली पारी में भी शतक लगाकर नाबाद (137 रन) रहे थे और भारत को अच्छी स्थिति में पहुंचाने का काम किया था। ध्रुव जुरेल ने दूसरी पारी में भी टीम को मुसीबत से निकालने का काम किया और अपना शतक पूरा किया। ये उनका दूसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ बैक-टू-बैक शतक रहा साथ ही ये उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर का 5वां शतक रहा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टिएटि से पहले ध्रुव का लय में आना टीम इंडिया के लिए काफी अच्छा संकेत है।

ध्रुव जुरेल का लगातार दूसरा शतक - दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में ध्रुव जुरेल ने अपना शतक 159 गेंदों पर पूरा किया। ध्रुव ने अपनी शतकीय पारी के दौरान 12 चौके लगाए। ध्रुव ने दूसरी पारी में हर्ष दुबे के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 250 गेंदों पर 184 रन की शानदार साझेदारी की। हर्ष दुबे ने भी टीम के लिए अच्छी पारी खेली और उन्होंने 116 गेंदों पर 84 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से एक छक्का और 12 चौके निकले। खबर लिखे जाने तक भारत ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 350 रन बना लिए हैं और टीम इंडिया की कुल बढ़त अब 384 रन की हो गई है। ऋषभ पंत पहले सेशन में रिटायर हट होकर मैदान से बाहर चले गए थे, लेकिन वो फिर से बैटिंग के लिए मैदान पर आ चुके हैं और बल्लेबाजी कर रहे हैं।

साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ ऋषभ पंत चोटिल

बेंगलुरु, एजेंसी। साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट मैच में भारत-ए के कप्तान ऋषभ पंत रिटायर्ड हर्ट होकर वापस लौटे, जिसने भारतीय फैंस को चिंता में डाल दिया है। पंत 14 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने जा रही टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का अहम हिस्सा हैं। शनिवार को मुकाबले के तीसरे दिन, पहले सेशन में साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज त्सेपो मोरकी की गेंद पंत के शरीर और

हेलमेट पर तीन बार लगी, जिसके बाद उन्हें भारत ए की दूसरी पारी के 34वें ओवर में रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा। उस समय तक पंत 22 गेंदों पर 17 रन बना चुके थे। ऋषभ पंत इस पारी में पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे। बार-बार गेंद लगने से पंत तकलीफ में थे। हर बार जब गेंद उनके बल्ले पर लगती, तो पंत दर्द में नजर आ रहे थे।

हालांकि, पंत बल्लेबाजी जारी रखने के लिए उत्सुक थे, लेकिन एहतियातन और फिजियो के कोच ऋषिकेश कानिटकर और फिजियो की अहम मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। ऋषभ पंत जुलाई में इंग्लैंड दौर पर मैनचेस्टर में खेले गए मुकाबले में चोटिल हुए थे। क्रिस गेंद लगने से पंत तकलीफ में थे। अंगुठे में फैक्चर के बाद उन्हें ठीक होने में करीब 98 दिनों का समय लगा।

सर्जरी के बाद पंत ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दो महीने रहिये और फिर भारत-ए के लिए खेलने से पहले सितंबर की शुरुआत में ट्रेनिंग शुरू की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर चुका है। 15 सदस्यीय टीम की कप्तान शुभमन गिल के हाथों में है। इस टीम में

विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत की वापसी हुई है। वह टीम के उपकप्तान भी हैं। बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 में जारी इस मुकाबले की बात करें, तो भारत-ए पहली पारी में 255 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका-ए ने पहली पारी में सिर्फ 221 रन बनाए। भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 53 ओवरों के अंदर 5 विकेट खोकर 175 रन बना लिए हैं। मेजबान टीम के पास फिलहाल 209 रन की लीड है।



सुल्तान अजलान शाह कप: भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा, संजय संभालेंगे कमान

नई दिल्ली, एजेंसी। सुल्तान अजलान शाह कप 2025 की शुरुआत 23 नवंबर से होने जा रही है। यह टूर्नामेंट 30 नवंबर तक मलेशिया के इपोह में आयोजित होगा। हॉकी इंडिया ने इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कप्तान संजय के पास है। टीम चयन को लेकर हेड कोच क्रैग फुल्टन ने कहा, सुल्तान अजलान शाह कप हमेशा से अंतरराष्ट्रीय हॉकी कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट रहा है। हम एक संतुलित टीम के साथ इसमें हिस्सा लेने के लिए उत्साहित हैं। हमारा फोकस अटैक और डिफेंस दोनों में अपनी संरचना को बेहतर बनाने, दुबाध में निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करने और पूरे खेल में निरंतरता बनाए रखने पर रहा है। उन्होंने कहा, इस टीम ने ट्रेनिंग में बेहतरीन

भारतीय टीम 29 नवंबर को कनाडा के खिलाफ मुकाबले के साथ अपने लीग चरण का समापन करेगी। यह टूर्नामेंट राउंड-रोबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें शीर्ष दो टीमों 30 नवंबर को होने वाले फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी। भारत ने आखिरी बार साल 2010 में सुल्तान अजलान शाह कप अपने नाम किया था। साल 2019 में भारत उपविजेता रहा। इस बार फैंस को टीम से काफी उम्मीद है।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। टीम चयन को लेकर हेड कोच क्रैग फुल्टन ने कहा, सुल्तान अजलान शाह कप हमेशा से अंतरराष्ट्रीय हॉकी कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट रहा है। हम एक संतुलित टीम के साथ इसमें हिस्सा लेने के लिए उत्साहित हैं। हमारा फोकस अटैक और डिफेंस दोनों में अपनी संरचना को बेहतर बनाने, दुबाध में निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करने और पूरे खेल में निरंतरता बनाए रखने पर रहा है। उन्होंने कहा, इस टीम ने ट्रेनिंग में बेहतरीन



एथलेटिक्स, बैडमिंटन, गोल्फ, जूडो, कराटे, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, कुश्ती और टेनिस में भाग लेंगे। खेल मंत्रालय ने भारतीय दल को मंजूरी दे दी है, और इसका पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी। मई 2022 में आयोजित पिछली डेफलिम्पिक्स ब्राजील में आयोजित पिछली डेफलिम्पिक्स प्रबंधन फर्मों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से एक करोड़ से अधिक के विज्ञापन सौदों में तब्दील हो जाएगा। इन खिलाड़ियों को अपने विज्ञापन का चेहरा बनाने के लिए कतार में लगे ब्रांडों में ऑटोमोबाइल कंपनियों से लेकर बैंक और एफएमसीजी तक शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा खेल सामग्री, जीवनशैली, सौंदर्य और अल्पकालिक अभियान के बजाय दीर्घकालिक साझेदारी पर ध्यान देते हैं। मंधाना, ऋचा घोष और राधा यादव का प्रबंधन करने वाली बेसलाइन वेंचर्स के एमडी और सह-स्थापक तुहिन मिश्रा तथा शेफाली और जेमिमा का प्रबंधन करने वाले जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के मुख्य वाणिज्यिक

टोक्यो डेफलिम्पिक्स 2025: टोक्यो डेफलिम्पिक्स के लिए भारत के 111 सदस्यीय दल की घोषणा

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय खिलाड़ी 11 खेलों, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, गोल्फ, जूडो, कराटे, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, कुश्ती और टेनिस में भाग लेंगे। खेल मंत्रालय ने भारतीय दल को मंजूरी दे दी है, और इसका पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी। मई 2022 में आयोजित पिछली डेफलिम्पिक्स ब्राजील में आयोजित पिछली डेफलिम्पिक्स प्रबंधन फर्मों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से एक करोड़ से अधिक के विज्ञापन सौदों में तब्दील हो जाएगा। इन खिलाड़ियों को अपने विज्ञापन का चेहरा बनाने के लिए कतार में लगे ब्रांडों में ऑटोमोबाइल कंपनियों से लेकर बैंक और एफएमसीजी तक शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा खेल सामग्री, जीवनशैली, सौंदर्य और अल्पकालिक अभियान के बजाय दीर्घकालिक साझेदारी पर ध्यान देते हैं। मंधाना, ऋचा घोष और राधा यादव का प्रबंधन करने वाली बेसलाइन वेंचर्स के एमडी और सह-स्थापक तुहिन मिश्रा तथा शेफाली और जेमिमा का प्रबंधन करने वाले जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के मुख्य वाणिज्यिक



लाखों से करोड़ों तक: आसमान छूने लगा भारत की महिला क्रिकेटर्स की ब्रांड वैल्यू

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत को महिला वनडे विश्व कप में पहली बार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली खिलाड़ियों का इसके बाद ब्रांड मूल्य भी आसमान छूने लग गया है और उनके पास पैसा कमाने का यह सबसे अच्छा मौका है। स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स जैसी खिलाड़ियों के ब्रांड मूल्य में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो उन्हें संभालने वाली प्रबंधन फर्मों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से एक करोड़ से अधिक के विज्ञापन सौदों में तब्दील हो जाएगा। इन खिलाड़ियों को अपने विज्ञापन का चेहरा बनाने के लिए कतार में लगे ब्रांडों में ऑटोमोबाइल कंपनियों से लेकर बैंक और एफएमसीजी तक शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा खेल सामग्री, जीवनशैली, सौंदर्य और अल्पकालिक अभियान के बजाय दीर्घकालिक साझेदारी पर ध्यान देते हैं। मंधाना, ऋचा घोष और राधा यादव का प्रबंधन करने वाली बेसलाइन वेंचर्स के एमडी और सह-स्थापक तुहिन मिश्रा तथा शेफाली और जेमिमा का प्रबंधन करने वाले जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के मुख्य वाणिज्यिक

अधिकारी करण यादव दोनों सवाल को जवाब में महिला क्रिकेटर्स को भविष्य के बारे में उत्साहित थे। यादव ने कहा, 'हम उनके ब्रांड मूल्य में तेज उछाल देख रहे हैं। शीर्ष स्तर की किसी खिलाड़ी के विज्ञापन मूल्य में दो से तीन गुना तक बढ़ोतरी हो गई है। जेमिमा की कीमत 60 लाख रुपये से बढ़कर लगभग 1.5 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। शेफाली की कीमत 40 लाख रुपये से बढ़कर लगभग एक करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। मिश्रा ने कहा, 'हमें शीर्ष खिलाड़ियों के लिए 25-55 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है। विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों के लिए यह आंकड़ा और अधिक हो सकता है। उन्होंने कहा, 'हमें यह भी उम्मीद है कि यह जीत वाणिज्यिक बाजार में महिला क्रिकेट को मजबूत करेगी, जहां ब्रांड अल्पकालिक अभियान के बजाय दीर्घकालिक साझेदारी पर ध्यान देते हैं। मंधाना, ऋचा घोष और राधा यादव का प्रबंधन करने वाली बेसलाइन वेंचर्स के एमडी और सह-स्थापक तुहिन मिश्रा तथा शेफाली और जेमिमा का प्रबंधन करने वाले जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के मुख्य वाणिज्यिक

दोगुनी 33 लाख हो गई है और शेफाली के फॉलोअर्स की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बड़ा बदलाव यह है कि ब्रांड अब उन्हें केवल क्रिकेट सत्र तक सीमित चेहरे के रूप में नहीं देखते हैं और इससे खिलाड़ियों के ब्रांड मूल्य में वृद्धि हो रही है। मिश्रा ने कहा कि महिलाएं उन ब्रांडों का प्रचार करके एक और सफलता हासिल करने के लिए तैयार हैं, जिनका प्रचार पारंपरिक रूप से पुरुष खिलाड़ी करते रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हम भारत में महिला खिलाड़ियों के लिए खेल सामग्री, जीवनशैली, सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल तथा शिक्षा जैसे विभिन्न उद्योगों में रुचि देख रहे हैं। उत्साहजनक बात यह है कि शीर्ष महिला क्रिकेटर अब उन क्षेत्रों में भी प्रवेश कर रही हैं जिन्हें पहले पुरुष-प्रधान माना जाता था। मिश्रा ने कहा, 'उदाहरण के लिए, स्मृति हुंड्रे, ग्लफ ऑयल, एस्वीआई बैंक, पीएनबी मेटलाइफ जैसे ब्रांडों से जुड़ी हैं, जो पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्र में हैं। इससे पता चलता है कि बाजार अब वास्तव में हमारी स्टा र महिला खिलाड़ियों की ताकत को समझता है।